बढ़ी है। इन सब कारणों से प्राइसज बढ़ रही हैं।

श्री मोतीभाई आर चौधरी : जब तक इस बारे में निर्णय न हो जाए, क्या तब तक प्राइसिज को बढ़ने दिया जाएगा ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मेम्बरों ने ही कहा था कि इस इस्यु को ब्यूरो आफ इंडस्ट्रियल कास्ट्स एंड प्राइसिज को रेफर किया जाए। इसी लिए वह उसको रेफर किया गया है। उसकी रीकमेंडशन आने के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं।

श्री मोतीभाई आर चौधरी : सरकार उसे जल्दी अपनी रीकमेंडेशन देने के लिए कहे।

श्री योगेन्द्र मकवाना : कहेंगे।

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER : In answar to the previous question, Government said that for the buffer stock they have to import wheat and rice from outside the country, So for better production of agricultural produce supply of fertilisers and insecticides to the agriculturits at subsidised retes is very necessary. So I demand that sufficient quantity of fertilisers and insecticides should be supplied to the agriculturists in varions States.

In this connection, I would like to mention that my State of West Bengal which is a defficit State is trying its best to produce more food. This year there is a good kharif crop and we are trying our best to have a better Boro and Rabi crop. But there is an acute shortage of fertilisers. So the agricultrists are unable to cultivate. So I would ask the Government not only to supply fertilisers and insecticides at subsidised rates to agriculturists but supply sufficient quantity of fertilisers to West Bengal and it should be sent immediatley so that the Boro and Rabi crop ean be cultivated in West Bengal in the interests of the nation.

SHRI YOGENDRA MAKWANA : There is no short supply. In fact there is adequate supply of fertilisers and insecticides to the State Government. The supply is also based on their demand. It is always decided before the season in consultation with the State and the supply is made to them.

So far as West Bengal Government is concerned, whatever thay have required, we have already supplied to them.

Fall In Prices Of Bajra

*83. †SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL :
SHRI RAM SINGH YADAV :

Will the Winister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the continued and steps fall in the prices of bajra;

(b) the existing selling price of bajra;

(c) whether the Food Corporation of India would purchase bajra at the support price and save the farmers from distress sale; and

(d) if so, the details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI M. S. SANGEVI RAO) : (a) and (b) It was reported that in Haryana, Rajasthan and Gujarat, the price of bajra had fallen below the support price of Rs. 124/—per quintal that had been announced by Government. However, with the entry of Food Corpration of India into the markets of those States, the prices of bajra have risen above the support prices. The prices in important producing centres like Gujarat range from Rs. 163 to Rs. 180 per quintal, in Maharashtra from Rs. 135. to Rs. 220, in Rajasthan from Rs. 132 to Rs. 140 and in Haryana from Rs. 125 to Rs. 132.

(c) and (d) Food Corpoation of India has already entered the markets of Gujarat, Haryana and Rajasthan. The

Corporation has also been advised to keep itself in readiness for entering the markets of any other State where the prices of bajra fall below the support price level.

श्री राम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय क्या मंत्री जी को मालूम है कि किसान ने अपनी फसल को बाजार में 15 अक्तूबर से बेचना शुरू किया और 15 अक्तूबर से 10 नवम्बर तक बाजरे की कीमत हरयाना और रास्थान की मंडियों में 85 रुपये क्विंटल से 115 रुपये क्विंटल थी ? क्या इस अवधि में अधिकतर किसानों ने जी अपनी फसल बेची है वह उस की डिस्ट्रेस सेल ही है ? इस भाव के मालूम होने के बाबजूद भी सरकार के एफ सी आई और दूसरी एजेंसीज के माध्यम से बाजरे की खरीद शुरू न करने का क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैं ने काल अटेंशन के उत्तर में कहा था, कोर्स ग्रेन की सपोर्ट प्राइस एनाउंस करने का अर्थ यह है कि किसानों को इस से कम दाम न मिले। ज्यों ही यह बात हम लोगों के ध्यान में आई कि कुछ राज्यों में बाजरे की कीमत रपोर्ट प्राइस से नीचे है सरकार ने 28 अक्तूबर को यह फैसला किया क्यों कि कोर्स ग्रेन के सम्बन्ध में यह आशा की जाती है, जो नियम अब तक है स्पोर्ट प्राइस देने के बाद, उस के अनुसार बाजारा, ज्वार और मेज के सम्बन्ध में कि राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में समुचित कदम उठाएंगी लेकिन ज्यों ही बाजरे की कीमत कम हुई तो हमने 28 अक्तूबर को फैसला किया इस बात का और उस के लिए तैयारी की। उसके बाद तमाम बाजारों में जा कर खरीद रहे हैं। प्रसन्नता की बात यह है कि सरकार का जो उद्देश्य था उस की पूर्ति इस प्रकार हुई कि जहां नहीं स्पोर्ट प्राइस से कम कीमत थी वहां वहां पर अब एवरेज क्वालिटी के बाजरे की कीमय स्पोर्ट प्राइस से ऊपर है।

श्री राम सिंह यादव : माननीय मंत्री जी ने यह नहीं बतलाया कि बाजरे की कीमत सपोर्ट प्राइस से नीचे जाने की सूचना क्या मंडियों से प्राप्त नहीं होती थी और यदि होती थी तो देरी से एफ सी आई के माध्यम से मंडियों में खरीद करने का क्या कारण है ? इस के साथ ही अब तक राजस्थान और हरयाने की मंडियों में एफ सी आई के माध्यम से कितनी खरीद की है और क्या वह खरीद आप ने किसानों से की या बीच के जो मझौले व्यापारी हैं उन से की है ?

श्री भागवत झा आजाद : मैंने यह बताया कि सरकार या एफ सी आई के बाजार में जाने का मतलब यह है कि जिन जिन मंडियों में कीमत सपोर्ट प्राइस से कम है वहीं हम खरीदते हैं। लेकिन मैंने पहले उत्तर में बताया कि सरकार के बाजार में जाने के बाद इन तमाम राज्यों की मंडियों में सपोर्ट प्राइस से ऊपर बाजारा बिक रहा है। अभी जब आप ने उस दिन काल अटेंशन के ऊपर बहुत जोर दिया तो हरयाने में हमने तीन स्पेशल टीमें कल और परसों भिजावाई। वहां से जो आंकड़े वह लाए और जो वहां के डायरेक्टर फूड स्टेटिस्टिक्स के आंकड़े हैं वह यह बताते हैं कि वहां की मंडियों में कीमत 130 से 132 तक है।

अध्यक्ष महोदय : फार योर इन्फामेंशन मैं यह कहूँगा कि आप सिरसा से पता करवएं, जो लेटेस्ट सूचना आप के पास है, वहां से आप अपनी जानकारी के लिए पता

करवाएं कि वहां क्या कीमत है और मुझे बता दें ताकि मालूम हो सके कि आफिशियल वर्जन क्या है और वैसे क्या है ?

श्री भागवत झा आजाद : हरयाना गवर्नमेंट जो स्टेटिस्टिक्स सरकार मब्लिश करती, है उस में उन्होंने कहा है कि जहां पर बाजरे की कीमत कम है स्पोर्ट प्राइस जो 124 रुपये है उससे वहां इस का कारण यह है कि बाजरे में स्वायश्चर अधिक है और नम्बर 2 डिसक्लर है तथा सब से दुर्भाग्य की बात यह है कि नेपा जिसको अर्गट कहते हैं जिस की टालरेंस लिमिट होनी चाहिए 25 और जो फगस हैं जो एक तरह का प्वायजन है वह उस में अधिक है, इस कारणों से इन बाजारों में नहीं खरीद पा रहे हैं ।

श्री राम सिंह यादव : यह नहीं बताया कि देर में बाजार में क्यों गए ?

श्री भागवत झा आजाद : मैंने बताया, आप ने सुना होता तो मालूम होता कि कोर्स ग्रेन के सम्बन्ध में सरकार ने सपोर्ट प्राइस फिक्स की लेकिन यह आशा की जाती है राज्य सरकारों से आप अपनी सरकार से भी कहिए, उन से आशा की जाती है जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट करती है, ज्यों ही कीमत कम होती है, महाराष्ट्र गर्वनमेंट तुरन्त खरीदती है, हमने यही राजस्थान और हरयाना के मुख्य मन्त्रियों से कहा था, जब उन्होंने नहीं खरीदा तो हम ने फैसला किया तैयारी की, बाजार में गए और खरीद की। इसलिए कुछ देर लगी। लेकिन आशा की जाता है कि कोर्स ग्रेन के सम्बन्ध में राज्य सरकारें समुचित कदम उठाएं क्यों कि यह लोकली कन्ज्यूम होने वाला ग्रेन है, इसलिए आल इंडिया लेबल या एफ सी आई से कुछ नहीं कर सकते हैं ।

श्री बुद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, एफ सी आई के मण्डी में आने से विशेष तौर से गुजरात और महाराष्ट्र में बाजरे की कीमत पर, जिसके भाव पहले गिर गए थे, असर पड़ा है और उससे किसानों को लाभ हुआ है। आपने बाजरे के सम्बन्ध में तो सपोर्ट प्राइस तय की लेकिन ज्वार और मक्का, जिसके भाव कोटा में बहुत गिर गए हैं, उस की सपोर्ट तय करने के सम्बन्ध में क्यों निर्णय नहीं लिया ?

श्री भागवत झा आजाद : इसका कारण यह है कि ज्वार और मक्के की कीमतें सपोर्ट प्राइस से अधिक हैं। अगर उनकी प्राइस से कम होती है तो उस स्थिति में राज्य सरकारों से आशा की जाती है कि वे आवश्यक कदम उठायेंगी ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिन राज्य सरकारों ने बाजरे की कीमत कम होने पर भी उसकी खरीद नहीं की उन राज्य सरकारों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे और किस प्रकार से आप मुआविजा देकर उन किसानों की क्षतिपूर्ति कर सकेंगे !

श्री भागवत झा आजाद : मैंने उस दिन बताया था कि गुजरात में तो भाव कम हैं लेकिन महाराष्ट्र और राजस्थान मे सपोर्ट प्राइस से ऊपर हैं और हम खुद ही एफ सी आई की तरफ से घूम रहे हैं कि हमें मिल जाए तो खरीद लें । सरकार राजस्थान में तो बाजरे की कीमत सपोर्ट प्राइस से अधिक है ।

Construction Of Rural And Urban Houses

SHRI N. K. SHEJWALKAR : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether any target has been